

National Task Force

On Mental Health of Students and Prevention of Suicides in Higher Education Institutions

द्वारा
छात्रों
फैकल्टी मेंबर्स
अभिभावकों
मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर
एवं शैक्षणिक संस्था प्रमुख

से मानसिक स्वास्थ्य पर एक सर्वे कराया जा रहा है
निम्न लिंक का प्रयोग करके सर्वे में सम्मिलित हों

<https://ntf.education.gov.in>

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(फोन - 0771-2636413, फैक्स - 0771-2263412)

(Email - highereducation.cg@gmail.com; Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्र. 120/ 51 /आउशि/न्या.प्र./2025

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 09/09/2025

प्रति,

अपर संचालक,

क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा,

रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर

विषय :- क्रिमिनल अपील क्रमांक 1425/2025 अमित कुमार एवं अन्य विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य।

संदर्भ :- उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 6-47/न्या.प्र./2025/38-2, दिनांक 29.08.2025 एवं दिनांक 08.09.2025

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में लेख किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स के अधिकारिक वेबसाइट URL: <https://ntf.education.gov.in> पर प्रश्नावली का प्रत्युत्तर भरा जाना है। प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान को नेशनल टास्क फोर्स वेबसाइट पर जाकर स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. के छात्रों, शिक्षकों अभिभावकों को भरने हेतु प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय टास्क फोर्स द्वारा सितंबर 2025 तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना है। इसलिए समस्त उच्च शिक्षण संस्थान इस प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए तत्काल सूचित करते हुए सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय टास्क फोर्स को सर्वेक्षण से संबंधित जानकारी दिनांक 12.09.2025 तक प्रस्तुत किया जाना है। अतः कृपया समय-सीमा के भीतर तत्काल अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाले शासकीय महाविद्यालयों को तत्काल निर्देशित करते हुए सभी शासकीय महाविद्यालयों को पोर्टल (<https://ntf.education.gov.in>) पर प्रश्नावली की जानकारी प्रविष्टी करवाकर उक्त कार्यवाही का पालन प्रतिवदेन दिनांक 10.09.2025 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि जानकारी दिनांक 12.09.2025 तक शासन को प्रेषित किया जा

अलग - उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

कार्यालय
अपर संचालक, उच्च शिक्षा
बिलासपुर (छ.ग.)अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

00

क्रमांक एफ 6-47 / न्या.प्र. / 2025 / 38-2

नवा रायपुर अटल नगर दि. 08/09/2025
08 SEP 2025

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इदावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।

- विषय:- क्रिमिनल अपील क्रमांक 1425/2025 अमित कुमार एवं अन्य विरुद्ध युनियन
ऑफ इंडिया एवं अन्य।
- संदर्भ:- 1. समसंख्यक पत्र दिनांक 29.08.2025
2. Government of India, Ministry of Education, Department of Higher
Education Dated 04.09.2025

00

- कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।
- 2/ उपरोक्त प्रकरण के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 04.09.2025 में उल्लेखित किया गया है कि, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स के अधिकारिक वेबसाइट URL:- <https://ntf.education.gov.in> पर प्रश्नावली का प्रत्युत्तर भरा जाना है। प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान को नेशनल टास्क फोर्स वेबसाइट पर जाकर स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. के छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों को भरने हेतु प्रोत्साहित करना है।
- 3/ राष्ट्रीय टास्क फोर्स द्वारा सितम्बर 2025 तक अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना है। इसलिए समस्त उच्च शिक्षण संस्थान इस प्रकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए तत्काल सूचित करते हुए सुनिश्चित करें कि, राष्ट्रीय टास्क फोर्स को सर्वेक्षण से संबंधित जानकारी 12.09.2025 तक प्रस्तुत किया जावे।
- 4/ अतः कृपया समय-सीमा के भीतर तत्काल अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(धनंजय नेताम)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

न्यायालयीन प्रकरण / महत्वपूर्ण

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

00

129 AUG 2025

क्रमांक एफ 6-47 / न्या.प्र. / 2025 / 38-2

नवा रायपुर अटल नगर दि. / 08 / 2025

प्रति,

आयुक्त,

उच्च शिक्षा संचालनालय,

इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।

विषय:- क्रिमिनल अपील क्रमांक 1425 / 2025 अमित कुमार एवं अन्य विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य।

00

विषयांकित प्रकरण में विषयांकित प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2025 के तहत राष्ट्रीय टास्क फोर्स द्वारा दिनांक 08.08.2025 को वेबसाइट URL:- <https://ntf.education.gov.in> लॉच किया गया। पोर्टल पर अंग्रेजी एवं हिन्दी में ऑनलाईन सर्वेक्षण प्रश्नावली उपलब्ध है। जिन्हें कैम्पस पर्यावरण, मौजूदा सहायता प्रणालियां एवं शिकायत निवारण तंत्र तथा छात्र कल्याण में सुधार के लिए सुझाव सहित विभिन्न विषयों पर गोपनीय जानकारी एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है।

3/ सर्वेक्षण के विभिन्न श्रेणियों के अतिरिक्त उच्च शिक्षा संस्थानों से जानकारी एकत्र करने के लिए संस्थागत सर्वेक्षण भी आयोजित किये जा रहे हैं, जिन्हें उच्च शिक्षा संस्थानों को सौंपे गए AISHE User Credetinal assigend to HEIs. के माध्यम से भरा जा सकता है।

4/ उक्त पत्र में अनुरोध किया गया है कि:-

1. वेबसाइट पर जाकर संबंधित सर्वेक्षणों में भाग लेना है।

2. प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत छात्रों, संस्थानों एवं अन्य हितधारियों के मध्य वेबसाइट लिंक एवं सर्वेक्षण की जानकारी का प्रचार-प्रसार करना है।

3. सर्वेक्षणों समय पर एवं निष्ठा से भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

5/ उपरोक्त पत्र के संदर्भ में कार्यवाही कर अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(धनंजय नेताम)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

14 AUG 2025

Secy. H. Edu.

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 13th August, 2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Launch of the Official Website of the National Task Force constituted pursuant to Supreme Court Judgment in Criminal Appeal No. 1425/2025 @ SLP (Crl) No. 13324/2024 titled *Amit Kumar & Ors Vs. Union of India & Ors* - reg.

Reference is invited to the constitution of the National Task Force by the Hon'ble Supreme Court of India, vide order dated 24.03.2025 to discuss and deliberate the issues related to mental health concerns among students, prevention of commission of the suicides in educational institutions and recommend preventive measures.

2. As part of its deliberations, the National Task Force has launched its website on 8th August 2025. The website serves as a central platform to gather diverse perspectives from key stakeholders including **Students** of Higher Education Institutions (HEIs); **Parents** of such students; **Faculty Members**; **Mental Health Service Providers**; and **Institutional Representative**. It also seeks inputs from General Public, including friends or family members of students affected by suicide, alumni, NGOs, media professionals, and other concerned citizens.

3. For more information and to participate in the survey, the website URL is <https://ntf.education.gov.in>.

4. The portal hosts structured online survey questionnaires, available in English and Hindi, designed to collect *anonymous* and *confidential* inputs on a wide range of themes including Campus environment; Inclusivity and belongingness; Sources of distress and systemic discrimination; Existing support systems and grievance redressal mechanisms; and Suggestions for improving student wellbeing.

5. Among different categories of Surveys, **Institutional Surveys** are also being conducted to gather information from Higher Education Institutions, which can only be filled in through **AISHE User Credential assigned to HEIs**.

6. All stakeholders are requested to:

- (i) Visit the website and participate in the relevant surveys;
- (ii) Disseminate the Website Link and survey information among Students, Institutions and other stakeholders under their administrative control;
- (iii) Encourage timely and sincere participation in the Surveys.

7. This may be given **PRIORITY** and **WIDE PUBLICITY** to encourage greater participation.

R. Sonowal
(Rina Sonowal Kouli)
Joint Secretary to the Government of India

To

1. All VCs/Directors of Centrally Funded Higher Education Institutions under MoE

2. All Higher Education Institutions through UGC
3. All Technical Institutions through AICTE
4. All Higher Education Institutions including INIs through respective Ministries/Departments
5. All Secretaries of Union Ministries of Government of India
6. All Chief Secretaries / Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries of Higher & Technical Education of States / UTs
7. Nominated Nodal Officers from States/UTs
8. Secretary, National Medical Commission
9. Chairman, Pharmacy Council of India
10. Chairman, Dental Council of India
11. Chairman, Indian Nursing Council
12. Chairman, Bar Council of India
13. Vice Chairman, NITI Aayog
14. Chairman, National Council for Teacher Education

Copy to, with a request to circulate the information to all Educational Institutions / Organisations / Bodies under their control and publicise it on the respective websites of their Ministry/Department:-

1. Secretary, M/o Home Affairs
2. Secretary, Department of School Education & Literacy, M/o Education
3. Secretary, Department of Social Justice & Empowerment, M/o Social Justice & Empowerment
4. Secretary, Ministry of Women and Child Development, Government of India
5. Secretary, Ministry of Health and Family Welfare
6. Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice
7. Vice Chancellor, NIEPA
8. All Bureau Heads, Department of Higher Education – with a request to ensure wide dissemination among concerned institutions.
9. CMIS/NIC – for uploading this OM on Ministry's website, NTF's website and e-Office.

Copy for Information to:

1. PS to Hon'ble Education Minister
2. PS to Hon'ble MoS for Higher Education
3. PPS to Secretary (Higher Education)
4. PPS to Joint Secretary (Higher Education)
5. Guard File – PN.II Section

ITEM NO.1502

COURT NO.13

SECTION II-C

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Criminal Appeal No.1425/2025 @ SLP(Crl.)No.13324/2024

AMIT KUMAR & ORS.

Appellant(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

Respondent(s)

[HEARD BY : HON. J.B. PARDIWALA AND HON. R. MAHADEVAN, JJ.]
IA No. 208458/2024 - EXEMPTION FROM FILING O.T.

Date : 24-03-2025 This appeal was called on for pronouncement
of judgment today.

For Appellant(s) :

Mr. Mehmood Pracha, Adv.
Mr. R. H. A. Sikander, AOR
Mr. Jatin Bhatt, Adv.
Mr. Sanawar, Adv.
Mr. Kshitij Singh, Adv.
Ms. Nujhat Naseem, Adv.
Mr. Sikander, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Brijender Chahar, A.S.G.
Ms. Mrinal Gopal Elker, AOR
Ms. Chhavi Khandelwal, Adv.
Ms. Shruti Verma, Adv.

Mr. Mukesh Kumar Maroria, AOR
Mr. Abhijit Pandove, Adv.
Mr. Amit Sharma Ii, Adv.
Mrs. Bani Dikshit, Adv.
Mr. Varun Chugh, Adv.
Mr. Gaurang Bhushan, Adv.

Signature Not Verified

Digitally signed by
CHANDRESEKAR
Date: 2025.03.24
19:45:04 IST
Reason: []

Crl.A.No.1425/2025

Ms. Mrinal Gopal Elker, Adv.
Ms. Chhavi Khandelwal, Adv.
Mr. Aditya Chaudhary, Adv.

1. The Bench comprising Hon'ble Mr. Justice J.B. Pardiwala and Hon'ble Mr. Justice R.M. Mahadevan pronounced the judgment.
2. Leave granted.
3. The relevant portion of the signed reportable judgment is as under:-

"69. The recurring instances of student suicides in Higher Educational Institutions, including private educational institutions, serve as a grim reminder of the inadequacy and ineffectiveness of the existing legal and institutional framework in addressing mental health concerns of students on campuses and to prevent the students from taking the extreme step of committing suicides. These tragedies underscore the urgent need for a more robust, comprehensive, and responsive mechanism to address the various factors which compel certain students to resort to taking their own lives. In light of the concerns expressed above, a National Task Force to address the mental health concerns of students and prevent the commission of suicides in Higher Educational Institutions is being constituted and shall comprise of the following members:

- i. Justice S. Ravindra Bhat, Former Judge, Supreme Court of India, as the Chairperson;
- ii. Dr. Alok Sarin, Consultant Psychiatrist, Sitaram Bhartia Institute of Science & Research, New Delhi;
- iii. Prof. Mary E. John (retired), Former Director, Centre for Women's Development Studies, New Delhi;
- iv. Mr. Arman Ali, Executive Director, National Centre for Promotion of Employment for Disabled People;
- v. Prof. Rajendar Kachroo, Founder, Aman Satya Kachroo Trust;
- vi. Dr. Aqsa Shaikh, Professor of the Department of Community Medicine in Hamdard Institute of Medical Sciences and Research, New Delhi;
- vii. Dr. Seema Mehrotra, Professor of Clinical Psychology, NIMHANS;
- viii. Prof. Virginus Xaxa, Visiting Professor at the Institute for Human Development (IHD), New Delhi;
- ix. Dr. Nidhi S. Sabharwal, Associate Professor, Centre for Policy Research in Higher Education, National University of Educational Planning and Administration, New Delhi;

x. Ms. Aparna Bhat, Senior Advocate (as *amicus curiae*). _

70. The following shall be the ex-officio members of this Task Force:

i. Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India;

ii. Secretary, Department of Social Justice & Empowerment, Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India;

iii. Secretary, Ministry of Women and Child Development, Government of India;

iv. Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, Government of India.

71. We direct the Chief Secretaries of all the States/Union Territories to nominate a high ranking officer, not below the rank of Joint Secretary in the Department of Higher Education of the respective State/Union Territory, to act as the nodal officer on behalf of the respective State/Union Territory. We further direct all the concerned departments/authorities of the respective State/Union Territory to cooperate with the nodal officer concerned and furnish necessary information, data and assistance as may be sought by such nodal officer.

72. The Joint Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India shall act as the convener of the Task Force.

73. The Task Force includes representatives from diverse fields to ensure an interdisciplinary approach to tackling the issue of commission of suicides in Higher Educational Institutions.

74. The remit of this Task Force is to prepare a comprehensive report that includes:

i. Identification of the predominant causes which lead to commission of suicides by students: An examination of the various causes which lead to student suicides in Higher Educational Institutions, including but not limited to ragging, caste-based discrimination, gender-based discrimination, sexual harassment, academic pressure, financial burden, mental health related stigma, discrimination based on ethnicity, tribal identity, disability, sexual orientation, political views, religious belief or any other grounds.

ii. Analysis of Existing Regulations: A thorough assessment of the effectiveness of current laws, policies, and institutional frameworks applicable to

Higher Educational Institutions concerning ragging, caste-based and gender-based discrimination, sexual harassment, mental health support, support for students facing academic challenges, financial support to students in need of funds, etc. This analysis will evaluate whether these frameworks adequately address the challenges faced by students.

iii. Recommendations for Strengthening Protections:

Proposing necessary reforms to the existing legal and institutional frameworks to ensure stronger enforcement, accountability, and preventive measures. The Task Force shall also put forth recommendations to address existing gaps, create a more inclusive and supportive academic environment, and ensure equal opportunities for members of marginalized communities.

75. In the process of preparing its report, the Task Force shall have the authority to conduct surprise inspections of any Higher Educational Institution. Additionally, the Task Force shall be at liberty to make further recommendations beyond the specified mandate, wherever necessary, to ensure a holistic and effective approach towards addressing mental-health concerns of students and eliminating the incidence of suicides in Higher Educational Institutions. The Task Force is

requested to take into account the views and concerns of all stakeholders, including those of student unions, whether elected or nominated and other student representative bodies, wherever they exist. The Task Force is also requested to seek representation from and consult the governments of all the States and Union Territories. The Task Force may also consider obtaining the views of the different stakeholders by way of circulating a questionnaire and seeking written responses thereupon.

76. It is clarified that the term "Higher Educational Institution" is used broadly to cover all higher educational institutions, including government and private universities, deemed to be universities, government and private colleges, etc.

77. The Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Education; the Secretary, Department of Social Justice & Empowerment, Ministry of Social Justice & Empowerment; the Secretary, Ministry of Women and Child Development; and the Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, Government of India, shall collaborate with the Task Force and extend full cooperation by providing all necessary information, documents, and resources required by the Task Force to effectively carry out its mandate.

78. The Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India shall serve as the Member-Secretary of the Task Force. The Ministry of Education, Government of India shall be responsible for providing all necessary logistical support to facilitate the functioning of the Task Force. This shall include making arrangements for travel, accommodation, and secretarial assistance, as well as covering all related expenses of the Task Force members. The Ministry shall provide a sufficiently large office space to the Task Force for holding its meetings and also to enable the officials to carry on its day-to-day activities. Additionally, the Ministry shall provide an appropriate honorarium to the members in recognition of their contributions.

79. We also direct that the Central Government, the Governments of all the States/Union Territories and agencies thereof, and Universities shall extend their full and active cooperation to the Task Force and provide the requisite data, information and assistance, as may be necessary. In the case of delay, reluctance or neglect on part of the aforesaid bodies, the Task Force will be at liberty to approach this Court through the *amicus curiae* seeking remedial actions.

80. The Chairperson of the Task Force shall be at liberty to engage the services of any person for the purpose of providing

secretarial assistance in coordinating with the members of the Task Force, preparation of the interim and final report and for the smooth and effective discharge of any other responsibilities as may arise during the course of carrying out the mandate of the Task Force. This shall include the engagement of the services of Data Analysts and Research Assistants as may be necessary for the effective discharge of the mandate of the Task Force.

81. The Chairperson of the Task Force shall also be at liberty to constitute, after due consultation with the members of the Task Force, committees and sub-committees as may be required for the purpose of carrying out specific functions.

82. We direct the Union of India to deposit an amount of Rupees Twenty Lacs (Rs 20,00,000/-) with the Registry within two weeks from the date of this order as an outlay for the initial operations of the Task Force. The *amicus curiae* shall be at liberty to move an appropriate application seeking orders for disbursement of any additional funds, whenever necessary. We clarify that this amount is in addition to the financial and administrative responsibility of the Ministry of Education as described aforesaid.

83. The Task Force is requested to present an interim report

within four months from the date of this order. The final report shall be submitted preferably within eight months from the date of this order.

84. We treat this matter as part heard. The registry shall notify this matter after four months alongwith the interim report of the Task Force before this very Bench (J.B. Pardiwala and R. Mahadevan, JJ.) after obtaining appropriate orders from Honourable the Chief Justice of India."

3. The matter is part heard in terms of the signed reportable judgment.

(CHANDRESH)
ASTT. REGISTRAR-cum-PS

(POOJA SHARMA)
COURT MASTER (NSH)

(Signed reportable judgment is placed on the file)